हिन्दी साप्ताहिक

न्यूज आइकॉन

T.C. NO. MAHHIN10172

संपादक - मुर्तुजा मामाजीवाला ईमेल: newsicon2021@gmail.com मूल्य: रु. - 2/-

वर्ष: 2 अंक: 12 पृष्ठ: 8 शुक्रवार,02 सितंबर से 08 सितंबर 2022

बालासाहेब की विरासत के लिए जंग

दशहरा रैली को लेकर क्यों भिड़े हैं उद्धव सेना और एकनाथ शिंदे ?

मुंबईः महाराष्ट्र में राजनीतिक फेरबदल की शुरूआत होने के बाद से ही शिवसेना के दोनों गुटों में तनातनी चल रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। अब दशहरा रैली के दौरान दोनों ही गुट अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दादर के शिवाजी पार्क में होने वाली यह रैली शिवसेना के लिए बहुत अहम है। 1966 से ही शिवसेना हर साल यहां दशहरा रैली करती रही है। दोनों ही गुट ओरिजिनल शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं। दशहरा रैली के जरिए उद्धव ठाकरे संदेश देना चाहते हैं कि शिवसैनिक अब भी उनके समर्थन में हैं लेकिन इसकी परमिशन को लेकर अभी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। उद्धव सेना की तरफ से 22 अगस्त को बीएमसी के पास ऐप्लिकेशन जमा किया है। उद्धव ठाकरे के गुट ने 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में रैली आयोजित करने की इजाजत मांगी है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि रैली के शेड्यूल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, शिवाजी पार्क में रैली होगी। बता दें कि बीएमसी हाउस का पिछला कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब फिर से चुनाव कराए जाने हैं। कई महीनों से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक ही महानगरपालिका के कामकाज देख रहा है। बीएमसी ने अब तक उद्धव ठाकरे के ऐप्लिकेशन पर कोई फैसला नहीं किया है। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि शिंदे सेना अपनी अलग ही दशहरा रैली करने की योजना बना रही है।

दोनों ही गुटों को इस रैली की अहमियत पता है। यह साल का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। 30 अक्टूबर सन 196 को पहली बार यह रैली शिवाजी पार्क में ही आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य साल भर के लिए पार्टी के कार्यकताओं और नेताओं के लिए अजेंडा सेट करना था।

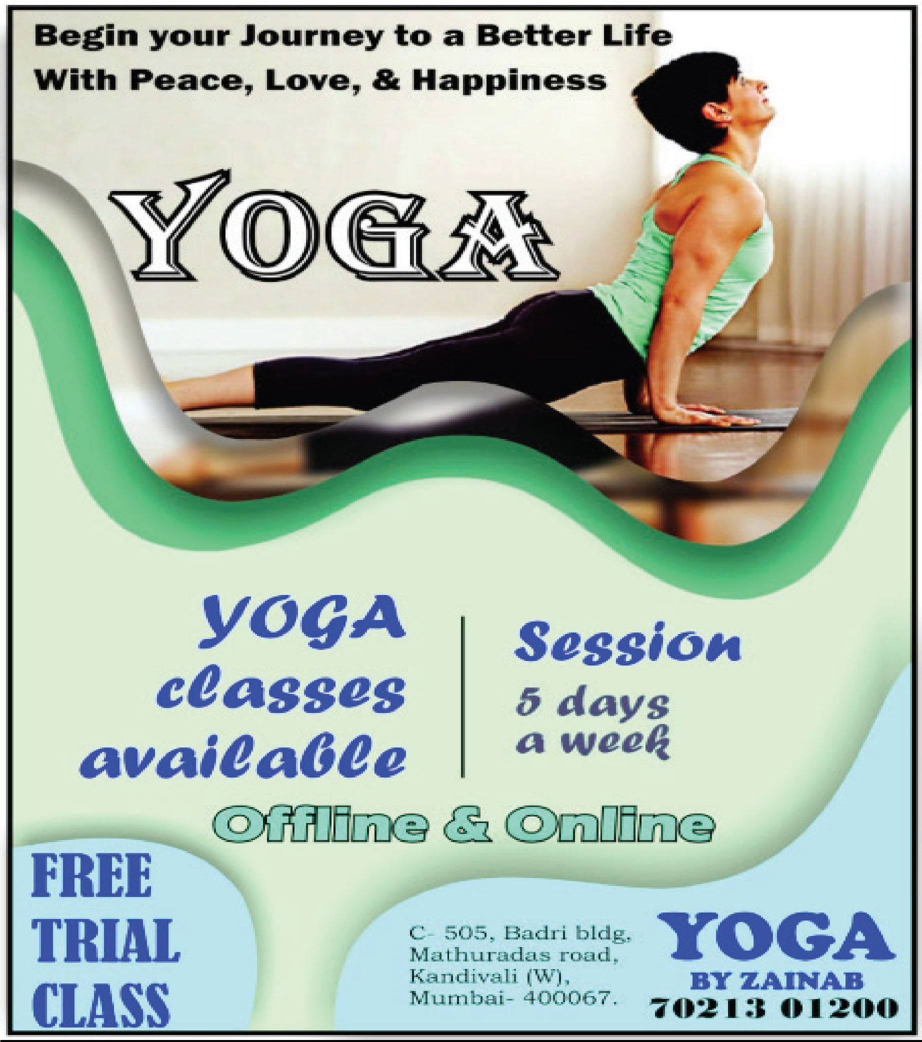

मुंबई में एक गणेश पंडाल के लिए 316 करोड़ रुपए का बीमा

सजावट में 60 किलो से अधिक सोने का इस्तेमाल

मुंबईः देश और महाराष्ट्र में बुधवार से दस दिवसीय गणेश चतुर्थी पर्व की शुरूआत हुई। पिछले दो साल के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के कारण यह त्योहार कई तरह की पाबंदियों के साए में मनाया गया था। महामारी का असर कम होने के बाद इस साल सार्वजनिक स्तर पर भव्य पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। एक से बढ़कर एक गणेश पंडाल स्थापित किए जाते हैं। लाखों रुपए खर्च कर बनाए जाने वाले पंडालों को बीमा भी कराया जाता है। ताकि किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई हो सके। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल मुंबई के सबसे अमीर गणेश मंडलों में से गौड़ सारस्वत ब्राह्मण सेवा मंडल को गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए 316.40 करोड़ रुपए का बीमा कवर मिला है।

इस सेवा मंडल की स्थापना 1955 में मध्य मुंबई के मांटुगा में किंग्स सर्कल के पास हुई थी।

एक स्वयंसेवक ने दावा किया है कि यह किसी मंडल की ओर से लिया गया अब तक सबसे ज्यादा बीमा कवर है। जीएसबी सेवा मंडल के अध्यक्ष विजय कामथ ने कहा, बीमा के तहत सभी सार्वजनिक देनदारियां और मंडल आने वाले प्रत्येक भक्त को 10 दिनों के उत्सव के लिए कवर किया जाता है। उन्होंने आगे कहा, ह्यमंडल ने भूकंप के जोखिम के साथ 1 करोड़ रुपए की मानक आग और विशेष जोखिम नीति भी ली है जिसमें फर्नीचर, जुड़नार, फिटिंग, कंप्यूटर, सीसीटीवी और स्कैनर जैसे इंस्टॉलेशन शामिल हैं। हम सबसे अनुशासित गणेश मंडल हैं, इसलिए बप्पा (भगवान गणेश) के हर भक्त को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है।316 करोड़ रुपए के बीमा में सोने, चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिए 31.97 करोड़ रुपए का कवर और पंडाल, स्वयंसेवकों, पुजारियों, रसोइयों, फुटवियर स्टाल, कर्माचरियों, वैलेट पार्किंग, व्यक्तियों और सुरक्षा गार्डों के लिए 263 करोड़ रुपए का व्यक्तिग बीमा कवर शामिल हैं।

दाऊद इब्राहिम के बारे में कई माह से जुटाई जा रही थी जानकारी

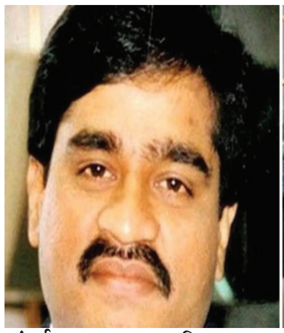

मुंबई। महाराष्ट्र पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता, एनआइए और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियां पिछले कई महीनों से भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों पर छापेमारी कर उसके संबंध में जानकारी जुटा रही थी। एनआइए द्वारा वीरवार को उठाया गया कदम इसी खोजबीन का परिणाम माना जा रहा है।पिछले महीने ही मुंबई एटीएस ने मुंबई के वसोर्वा उपनगर से टेरर फंडिंग मामले में दाऊद इब्राहिम गैंग के एक व्यक्ति परवेज जुबेर मेमन (47) को गिरफ्तार किया था। एटीएस सूत्रों के अनुसार, परवेज जुबेर ने स्वीकार किया है कि वह नशीले पदार्थों व अन्य अवैध कारोबार से प्राप्त धन आतंकी गतिविधियों में लगे प्रतिबंधित संगठनों को उपलब्ध कराता रहा है। जुबेर को दाऊद के भाई अनीस का करीबी बताया गया है। एटीएस ने अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही अनीस इब्राहिम व कुछ अन्य के खिलाफ भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में आईपीसी की धारा 121(ए) तथा गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) की धाराओं 17, 18 के तहत एफआइआर दर्ज की थी।

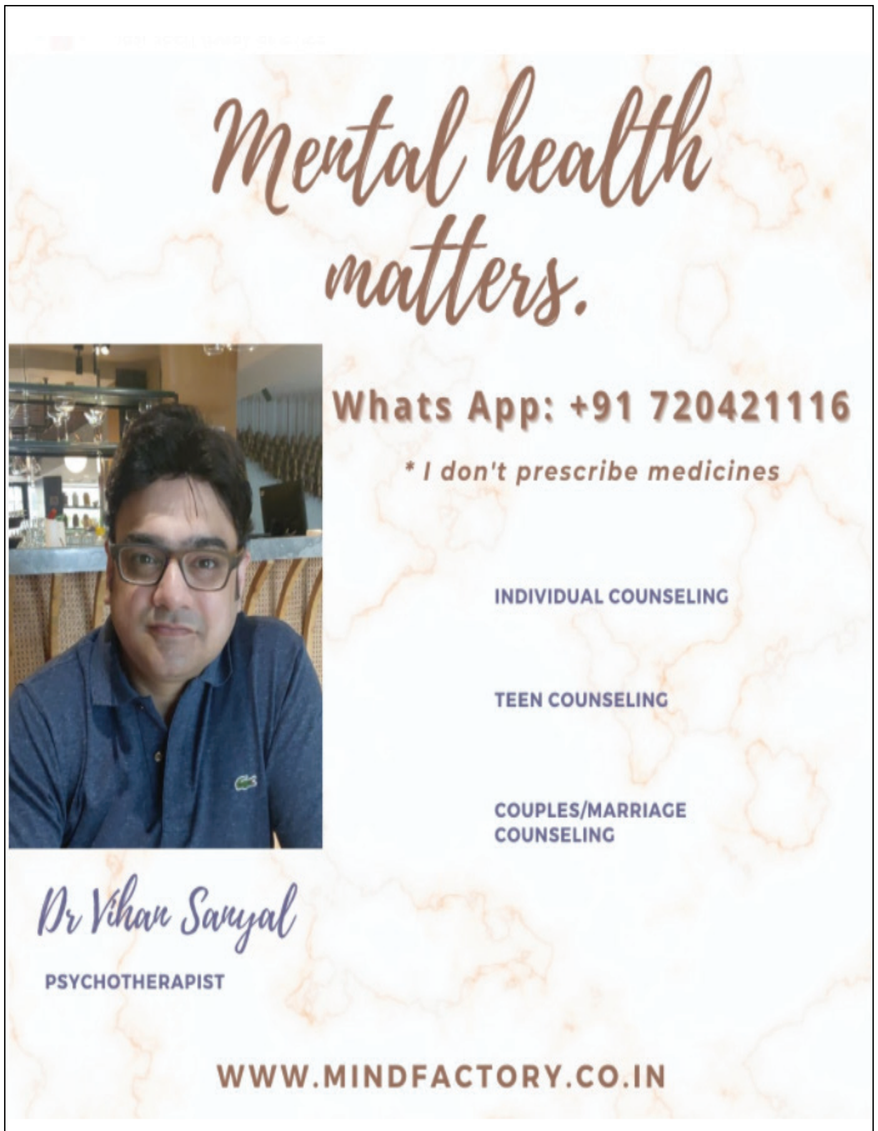

मुंबई की जर्जर इमारत में रहने को मजबूर 100 परिवार, 2020 में कट गया था बिजली और पानी

मुंबई मुंबई के जीटीबी नगर की पंजाबी कॉलोनी के निवासियों पर मौत का साया 24 घंटे मंडरा रहा है। लगभग 100 परिवार जर्जर ढांचे में रहने को मजबूर है, इनका जीवन जोखिम से भरा है क्योंकि वे कहीं और एक फ्लैट लेने में असमर्थ हैं।

इसमें 1,200 अपार्टमेंट हैं और अधिकांश लोग खतरे को देखते हुए यहां से बाहर जा चुके हैं।पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के शरणार्थियों के लिए 1958 और 1962 के बीच निर्मित, चार मंजिला ये इमारत में हमेशा रौनक रहा करती थी। जैसे-जैसे वर्षों की उपेक्षा के बाद इमारत में दरारें आने लगीं, उसके पुनर्विकास करने के प्रयास किसी न किसी कारण से आगे नहीं बढ़ सका। इससे भवनों की स्थिति और भी खराब हो गई।

19 अगस्त को बोरीवली में गीतांजलि इमारत के पांच परिवारों के इमारत छोड़ने के बाद से पंजाबी कॉलोनी फिर से ध्यान में आ गई है। शहर में 350 से अधिक खतरनाक इमारतें हैं। बीएमसी ने 2020 में पंजाबी कॉलोनी में पानी और बिजली की आपूर्ति काट दी।तीसरी मंजिल पर रहने वाली सुमन कोचड़ का कहना है कि उनके पति अशोक लकवाग्रस्त हैं। ह्वह पिछले तीन वर्षों से बिस्तर पर है। कुछ साल पहले हमारी बेटी की शादी हुई थी। सुमन ने कहा, अब हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है और हम 15 हजार - 20 हजार का किराया नहीं दे सकते। हम बहुत चिंतित हैं लेकिन हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते। ह्वसब्जी, दूध और किराना विक्रेता खुले बीम के कारण इमारतों में प्रवेश करने से मना कर देते हैं और बारिश से जर्जर दीवारों पर दरारों से पौधे निकल आते हैं। ह्वमेरे पास एक लंबी रस्सी से बंधा एक बैग है। मैं इसे विक्रेताओं से आवश्यक सामान लेने के लिए छोड़ देती हूं। हरमिंदर सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ इसी इमारत में रहते हैं। उनका भी स्वास्थ्य भी खराब रहता है और आर्थिक रूप से भी वे तनावग्रस्त हैं, हरमिंदर ने बताया कि वे बचपन से इस घर में रह रहे हैं। जबकि हमारे सभी पड़ोसी पहले ही जा चुके हैं। कोई भी ऐसी परिस्थितियों में नहीं रहना चाहता लेकिन अधिकारियों को हमें जाने के लिए कहने से पहले सोचना होगा। हम इतना किराया कैसे देंगे? हरमिंदर जैसे कई लोगों ने तत्काल किराए या वैकल्पिक आवास की मांग की है। बीएमसी द्वारा इमारतों की जर्जर हालत का हवाला देते हुए पंजाबी कॉलोनी को नोटिस जारी करने के दो साल बाद इंद्रपाल बागी इंदौर चले गए। ह्वसंरचनाओं के पुनर्विकास को लेकर अभी भी मारामारी है हालांकि हमारे स्थानीय नेता ने हमारी मदद की, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। अधिकारियों के लिए लोगों को खाली करने के लिए नोटिस भेजना आसान है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किराये के आवास का खर्च नहीं उठा सकते हैं। वे अभी भी बिजली और पानी के बिना रह रहे हैं और अपने जीवन के लिए डर रहे हैं

ह्व नवी मुंबई में किराए पर रहने वाले पुष्कर रावत ने कहा कि परिसर खाली करने का दबाव हर दिन बढ़ रहा है।

मुंबई में अरबों रुपये का पीएफ घोटाले का खुलासा, सीबीआइ जुटा रही जानकारियां

मुंबई। सीबीआइ ने 'जेट के करोड़ों के पीएफ का घोटाला' शीर्षक से मिड-डे के 20 अगस्त के अंक में प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संबंध में अखबार के कार्यालय से संपर्क साधा और कई जानकारियां जुटाई।

एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि हम मिड-डे की खबरों पर नजर रख रहे हैं। हम उन लोगों से बात कर रहे हैं, जिनका आपने हवाला दिया है।मुंबई के कांदीवली क्षेत्र स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आफिस में तैनात सोशल सिक्योरिटी अफसर व कुछ अन्य कर्मियों ने फर्जी तरीके से क्लेम कर काफी कर्मचारियों के कई सौ करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। पीड़ितों में जेट एयरवेज के पायलट, चालक दल के अन्य सदस्य व कर्मी भी शामिल हैं। यह खबर मिड-डे ने ब्रेक की थी।इस बीच, मामला सामने आने पर ईपीएफओ ने आरोपित अधिकारी बामने को तुरंत निलंबित कर दिया है और पूरे मामले कि विस्तृत जांच के लिए उच्च अधिकारी को नियुक्त किया है। सूत्रों के अनुसार यह घोटाला तीन साल से चल रहा था लेकिन महामारी के दौरान लाकडाउन में इसमें तेजी आई। मामला सामने आने पर अब ईपीएफओ जेट एयरवेज के पायलटों व अन्य कर्मियों से संपर्क कर उनसे पैन कार्ड और बैंक चेक मांग रहा है, ताकि उन्हें पीएफ के पैसे लौटा सके।केंद्रीय जांच एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि सीबीआइ ने स्थिति का जायजा लेने के लिए सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज (सीबीटी) से भी संपर्क किया है। उधर, ईपीएफओ के सूत्रों ने बताया कि भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारी मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रहे हैं और सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। सीबीआइ के अधिकारी ने कहा कि हम सुबूत खोजने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हैं ताकि आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सके। यह पूछे जाने पर कि ईपीएफओ के आरोपित कर्मियों की ओर से सुबूत मिटाने की कोशिश हो सकती है, पर उन्होंने कहा कि अगर हमें सुबूत मिटाने के निशान मिलते तो उनके खिलाफ नया मामला दर्ज किया जाएगा।

महाविकास आघाड़ी का एक और फैसला

पलटने को तैयार शिंदे सरकार, अब इस परियोजना में बदलाव के संकेत

मुंबई। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के हालिया फैसलों से लग रहा है कि वह पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी (एमवीए) का एक और फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए हैं कि एमवीए सरकार द्वारा बनाई गई भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना में बदलाव किया जाएगा। इस परियोजना को एसबीयूटी परियोजना भी कहा जाता है। इधर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी) को काम रोकने के लिए स्टाप वर्क नोटिस जारी किया है। सी वार्ड के सहायक आयुक्त किशोर येरामे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि नोटिस में कहा गया है कि चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।राज्य सरकार ने बुधवार को भिंडी बाजार की पुनर्विकास परियोजना मामले में जांच की घोषणा की थी। फडणवीस ने कहा कि परियोजना में बदलाव करके एसबीयूटी की कई अनियमितताओं को दूर किया जाएगा।

संपादकीय

संपादक - मुर्तुजा मामाजीवाला

सड़क हादसों का जारी सिलसिला

सड़क हादसों को लेकर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट चिंतित और साथ ही निराश करने वाली भी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष मार्ग दुर्घटनाओं में डेढ़ लाख से अधिक लोगों की जान गई। इसका अर्थ है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे आयोजनों और मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के अन्य प्रयास नाकाम सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक यह आंकड़ा एक लाख मौतों के करीब था। मार्ग दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ना इसलिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कई ऐसे देशों के मुकाबले भारत में वाहनों की संख्या उतनी नहीं, जहां कहीं कम सड़क हादसे होते हैं।एनसीआरबी के अनुसार करीब 60 प्रतिशत सड़क हादसे वाहनों की तेज गति के कारण होते हैं। इस कारण के मूल में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यातायात नियमों की अनदेखी, गलत और कई बार तो उलटी दिशा में वाहन चलाने, अतिक्रमण एवं सड़कों की खराब डिजाइन के कारण भी हादसे होते हैं। इसी तरह सड़कों के गड्ढे भी मार्ग दुर्घटना का कारण बनते हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों का संकल्प महज एक नारा बनकर रह गया है। प्रायः प्रमुख सड़कों पर भी महीनों तक गड्ढे बने रहते हैं। उनके कारण हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन जिन पर सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है, वे चेतते ही नहीं।एनसीआरबी के आंकड़े यह भी कह रहे हैं कि सड़कों की लंबाई में केवल 2.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में 30 प्रतिशत से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, वैसे-वैसे मार्ग दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि सड़क हादसों के मूल कारणों की पहचान कर उनका प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाए। इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों और उनकी यातायात पुलिस को भी सजगता दिखानी होगी। इसके अलावा सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभागों को भी जवाबदेह बनाना होगा। अभी यह जवाबदेही केवल कागजों तक सीमित है। इसी कारण सड़कों पर दुर्घटना बहुल स्थलों की पहचान होने के बाद भी समय रहते अपेक्षित कदम नहीं उठाए जाते।

एक तथ्य यह भी है कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती। सड़क हादसों को रोकने के उपायों पर इसलिए प्राथमिकता के आधार पर अमल होना चाहिए, क्योंकि इन हादसों में अधिकतर उनकी जान जाती है, जो अपने परिवार के कमाऊ सदस्य होते हैं। इससे वह परिवार गंभीर संकट से घिर जाता है। यह संकट समाज के साथ राष्ट्र को भी प्रभावित करता है।

सरकार का काम नहीं उसे निर्देश देना

.जब आपराधिक जांच की बात आती है, तो किस व्यक्ति की जांच की जानी है। किस धारा के अंतर्गत उसकी जांच की जानी है, किसी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य की मात्रा क्या है, किस पर आरोप लगाना है और किस पर आरोप नहीं लगाना है, जैसे मामलों में सीबीआई सरकार अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। यह इसलिए उत्तरदायी नहीं होगी, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। न्यायालय विधियां निर्धारित नहीं करते हैं। न्यायालय सरकार की प्रशासनिक नीतियों का निर्णय करने के लिए नहीं हैं। न्यायालय विधानों का निर्णय करने के लिए नहीं हैं। इसी प्रकार, संसद अभियुक्त के दोष अथवा निर्दोष का निर्णय करने के लिए नहीं है। इसका निर्णय न्यायालयों को करना है, न कि अन्य एजेंसियों को करना है। ...आज प्रश्न यह है, पूरा मुद्दा यह है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किस अपराध के अंतर्गत... आरोप तय करना है। कानून की विधिवत प्रक्रिया का पालन कर लखनऊ में निर्धारित आरोप को अस्वीकार कर दिया गया है, आरोप पत्र पुनः रायबरेली न्यायालय में भेज दिया गया।

दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि सरदार सिमरनजीत सिंह मान द्वारा अंत में पूछा गया प्रश्न विचार करने योग्य है। उन्होंने कहा था, हमें इस सभा में सभी जांच एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा प्रारंभ करनी चाहिए, चाहे वह रॉ, सीबीआई, आईबी इत्यादि हो। मैं अन्य जांच एजेंसियों की भूमिका में नहीं जा रहा हूं। ठीक इसी प्रकार दासमुंशी ने एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था, जब वह मेरे मित्र प्रमोद महाजन द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में उत्तर पढ़ रहे थे। प्रश्न था, सीबीआई किन मामलों में सरकार से अनुमति या स्वीकृति प्राप्त करती है? और उत्तर था : कानून के अनुसार, जब कभी भी अनुमति अपेक्षित होती है, सिर्फ उन्हीं मामलों में अनुमति मांगी जाती है। .सीबीआई एक सांविधिक एजेंसी है। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्र सरकार की पुलिस के रूप में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत सीबीआई का गठन हुआ था, परंतु वर्षों से सीबीआई का कार्य-बोझ काफी बढ़ गया है तथा हमारे कानून और संघीय ढांचे के तहत कानून व्यवस्था और जांच का कार्य राज्यों का है। इसलिए सीबीआई के पास स्वयंमेव ही यह अधिकार नहीं है कि वह राज्य में अपनी मर्जी से किसी मामले की जांच करे। ऐसा करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित होती है।

अब ऐसे अनेक मामले हैं, जिन्हें न्यायालय जांच हेतु सीधे सीबीआई को भेज देते हैं। आज जांच एजेंसी के रूप में सीबीआई के पास काफी कार्य है, किंतु वह प्रशासनिक रूप से सरकार के विशेष विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रति भी उत्तरदायी है। वर्तमान में यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है, यद्यपि यह विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। इस प्रकार, एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जिसे सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने उठाया है कि सीबीआई से संबंधित ऐसे कौन-से मामले हैं, जिनमें सरकार निर्णय ले सकती है।

सीबीआई को वास्तव में किन मामलों में सरकारी अनुमति अपेक्षित होती है और इस सभा में सीबीआई के किन कार्यों पर चर्चा की जा सकती है। यदि सीबीआई के कार्यकरण से संबंधित कतिपय प्रशासनिक मामले हों, तो विभिन्न अनुमतियां लेनी अपेक्षित होती हैं। जहां तक प्रशासनिक कार्यकरण का संबंध है, सीबीआई का आकार क्या होना चाहिए, सीबीआई को सौंपे जाने वाले मामले किस प्रकार के होने चाहिए, सीबीआई को राज्य सरकारों से मंजूरी लेने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ...जब आपराधिक जांच की बात आती है, तो किस व्यक्ति की जांच की जानी है। किस धारा के अंतर्गत उसकी जांच की जानी है, किसी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य की मात्रा क्या है, किस पर आरोप लगाना है और किस पर आरोप नहीं लगाना है, जैसे मामलों में सीबीआई सरकार अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। यह इसलिए उत्तरदायी नहीं होगी, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। न्यायालय विधियां निर्धारित नहीं करते हैं। न्यायालय सरकार की प्रशासनिक नीतियों का निर्णय करने के लिए नहीं हैं। न्यायालय विधानों का निर्णय करने के लिए नहीं हैं। इसी प्रकार, संसद अभियुक्त के दोष अथवा निर्दोष का निर्णय करने के लिए नहीं है। इसका निर्णय न्यायालयों को करना है, न कि अन्य एजेंसियों को करना है।

...आज प्रश्न यह है, पूरा मुद्दा यह है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किस अपराध के अंतर्गत... आरोप तय करना है। कानून की विधिवत प्रक्रिया का पालन कर लखनऊ में निर्धारित आरोप को अस्वीकार कर दिया गया है, आरोप पत्र पुनः रायबरेली न्यायालय में भेज दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो उस आरोप पत्र के अनुसार, अभियोजन कार्यवाही कर रहा है। किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कार्यवाही करनी चाहिए, किस आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कार्यवाही करनी चाहिए, यह ऐसा मामला है, जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना है न कि संसद द्वारा। ...मेरा केवल इतना कहना है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश देना सरकार का काम नहीं है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की आलोचना करना विपक्ष का काम नहीं है, अपनी क्रियाविधियों का अनुसरण करने का कार्य स्वयं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, प्राइवेट स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की समीक्षा हर साल करे सरकार

लखनऊः विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मुफ्त शिक्षा देने वाले प्राइवेट स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति की प्रति वर्ष समीक्षा करने का आदेश दिया है। अभी ऐसे प्राइवेट स्कूलों को साल 2013 में नियत प्रति छात्र के हिसाब से 450 रुपये प्रति माह ही दिया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि हर कैलेंडर साल के 30 सितंबर को सरकारी व स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों के कुल छात्र अनुपात को उन पर प्रति वर्ष किए जाने वाले सरकारी खर्चे से विभाजित करके आने वाली राशि को ध्यान में रखकर प्रतिपूर्ति तय की जाए। यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने लखनऊ एजुकेशन एंड ऐस्थेटिक डेवलपमेंट सोसायटी की ओर से दाखिल रिट याचिका पर पारित किया।

याची की ओर से अधिवक्ता पीके सिन्हा व एसएल वैश्य का तर्क था कि सरकार ने अधिनियम व इसके तहत 2011 में बने नियमों के तहत 20 जून 2013 को प्रतिपूर्ति नियत की थी और अभी वही चली आ रही है जबकि यह किसी से छिपा नहीं है कि तब से हर चीज की कीमतें कितनी अधिक बढ़ गयी है। कहा गया कि 2013 में नियत 450 रुपये प्रति छात्र प्रतिपूर्ति उचित नहीं है।ट हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को प्रति साल प्रतिपूर्ति की समीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक ओर तो सरकार अधिनियम की मंशा के अनुरूप पर्याप्त संख्या में स्कूलों की स्थापना नहीं कर पा रही है और दूसरी ओर जो स्कूल छात्रों को मुफ्त शिक्षा दे रहें हैं, उन्हें फीस की प्रतिपूर्ति करने में भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

एएसपी बागपत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश

मेरठ। अपर जिला जज हर्ष अग्रवाल ने एएसपी बागपत मनीष कुमार मिश्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ को दिए हैं। एक मुकदमे में एएसपी की गवाही होनी थी लेकिन सूचना देने के बाद भी वह न्यायालय नहीं पहुंचे। अदालत की अवहेलना मानते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया है। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-15 में सरकार बनाम दर्पण अंतर्गत धारा 304बी का मुकदमा चल रहा है। वर्तमान में अभियुक्त जेल में बंद है। मुकदमे में सभी गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, केवल बागपत के एएसपी मनीष कुमार मिश्र का साक्ष्य संकलित किया जाना शेष है। वह इस मुकदमे में अंतिम गवाह हैं। आठ सितंबर 2021 से एएसपी को न्यायालय में तलब किया जा रहा है लेकिन वह बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। न्यायालय द्वारा एएसपी के मोबाइल पर भी संपर्क कर उन्हें मामले से अवगत कराया गया लेकिन उन्होंने ला एंड आर्डर की ड्यूटी में व्यस्तता की बात कही। इस बाबत एएसपी की तरफ से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी की अर्जी पर न्यायालय ने इसे आदेशों की अवहेलना माना। अदालत ने पुलिस महानिदेशक लखनऊ को आदेशित किया है कि वह आठ सितंबर-2022 तक एएसपी मनीष कुमार मिश्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करें।

बिहार में महंगा होगा बालू, सरकारी कार्यालयों में अगले साल 36 अवकाश; कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

पटना। बालू की कीमत फिर बढ़ने की आशंका है। राज्य सरकार ने प्रदेश की पांच नदियों से निकाले जाने वाले बालू की रायल्टी में दोगुनी वृद्धि कर दी है। किउल, सोन, मोरहर, फल्गु एवं चानन से लाल बालू मिलता है। पूर्व में इन सभी नदियों से रायल्टी के रूप में प्रति घनमीटर 75 रुपये लिए जाते थे। अब प्रति घनमीटर 150 रुपए रायल्टी ली जाएगी। यही नहीं अनुममंडलीय स्तरीय समिति द्वारा तैयार एवं सिया से अनुमोदित बालू घाटों का बंदोबस्त शुल्क अलग से निर्धारित किया जाएगा। मंगलवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खनन विभाग के दो प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा अभियान के नियोजित शिक्षकों के वेतन मद के लिए राज्य संसाधन से 94 अरब रुपए भी स्वीकृत किए हैं। आज की बैठक में कुल आठ प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में निर्माण व भराई कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में बालू उपलब्ध है। अनुमंडलीय स्तरीय समिति द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसका अनुमोदन राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार (सिया) ने किया है। सर्वेक्षण में चिन्हित बालू घाटों में खनन योग्य बालू की मात्रा निर्धारित है।

बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, नीतीश कैबिनेट के फैसले से लाखों टीचरों को होगा फायदा

पटना : राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य स्कीम मद से 94 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। केंद्र सरकार ने वेतन मद में पर्याप्त राशि नहीं मिलने की वजह से राज्य स्कीम से यह राशि जारी की गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने 2023 के सरकारी अवकाश की स्वीकृति भी दे दी है। राज्य कर्मियों को 2023 में कुल 34 छुट्टियां प्राप्त होंगी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत पंचायती राज संस्था, नगर निकाय के साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में 264620 शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक नियोजित किए गए हैं। इनके वेतन का भुगतान का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। लेकिन बिहार को वेतन मद में केंद्र सरकार से पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा। लिहाजा सरकार ने राज्य योजना मद से 94 अरब 40 लाख रुपया स्वीकृत किया है। मंत्रिमंडल ने 2023 के लिए सरकार कर्मचारियों के लिए अवकाश स्वीकृत कर दिया है। कार्यपालक आदेश के तहत कर्मियों के लिए15 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसमें तीन अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। इसी प्रकार 20 प्रतिबंधित-ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत किए गए हैं। इसमें नौ अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। ऐच्छिक अवकाश में अधिकतम तीन अवकाश का ही उपभोग किया जा सकता है.

कविता

कहै कबीर दीवाना-ओशो

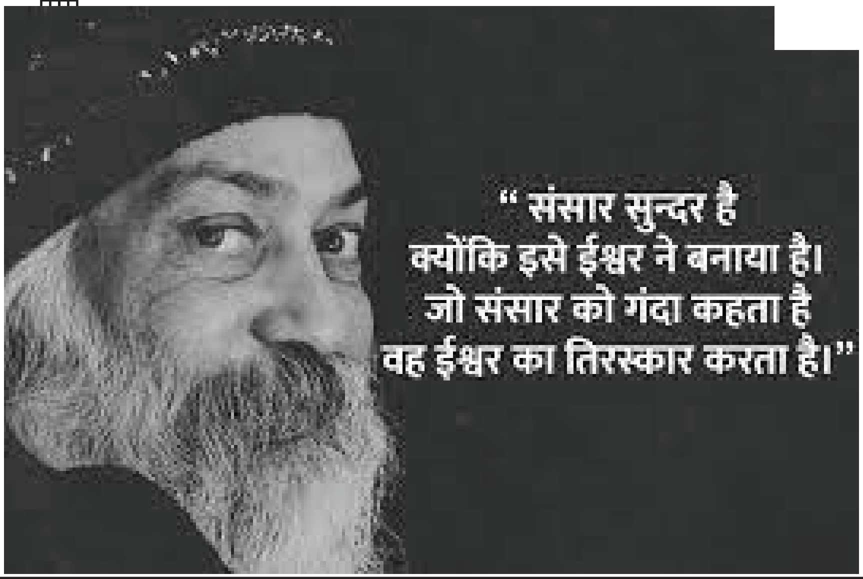

एक अनूठी प्यास कंठ को पकड़ लेती है। प्राण जकड़ जाते हैं। अब तुम तड़फते हो, जैसे मछली तड़फती है। पानी से निकाल ली किसी ने मछली को और डाल दी रेत पर; और तड़फती है। ऐसा गुरु तुम्हें पहली दफा तुम्हें तुम्हारे गलत प्रेम से निकाल कर ठीक प्रेम की रेत पर डाल देता है। तुम तड़फते हो। पहली दफा विरह की अग्नि पैदा होती है।

प्रीति लागी तुम नाम की, पल बिसरे नाही।
नजर करो अब मिहर की, मोहि मिलो गुसाई।।
बिरह सतावै मोहि को, जिव तड़फे मेरा,
तुम देखने की चाव है, प्रभु मिला सबेरा।।
विरह सतावै मोहि को, जिव तड़फे मेरा--

प्राण तड़फते हैं तुम्हारे लिए। श्वास चलती है तुम्हारे लिए। पलभर को भी विश्राम नहीं है। याद चुभती है कांटों की तरह **जारी...**

बादाम और काली मिर्च साथ में खाने से मिलते हैं ये 8 फायदे

हम सभी बादाम और काली मिर्च का सेवन करते हैं, लेकिन अलग-अलग। दोनों का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी दोनों का साथ में सेवन किया है? हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं, कि बादाम और काली मिर्च का सेवन करने से सेहत को अद्भुत फायदे मिलते हैं। बादाम और काली मिर्च साथ में खाना कैसे फायदेमंद है और इससे सेहत को क्या फायदे मिलते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन गरिमा गोयल से बात की। इस लेख में हम आपको बादाम और काली मिर्च खाने के 8 फायदे बता रहे हैं।

बादाम में स्वास्थ्य के लिए जरूरी विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, यह डाइट्री फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ई, प्रोटीन, मैंगनीज, कॉपर और फास्फोरस जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। साथ ही इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मौजू होते हैं। वहीं काली मिर्च की बात करें तो यह पोषक तत्वों के साथ ही कई औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है। इसमें विटामिन ए, सी, फ्लेवोनोइड्स, कैरोटीन के साथ ही कई अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इस तरह बादाम और काली मिर्च का साथ में सेवन करने से न सिर्फ शरीर को जरूर पोषण मिलता है, बल्कि इससे गंभीर रोगों को दूर रखने और उनके जोखिम को कम करने में भी मदद मिलती है।बादाम को ब्रेन फूड कहा जाता है, क्योंकि यह दिमाग को तेज और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। वहीं काली काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन चिंता और तनाव जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। यह कॉम्बिनेशन डिप्रेशन से लड़ने में भी कारगर है।

यह ब्रेन फंक्शन को बेहतर और दिमाग को एक्टिव करने में मदद करता है।बादाम और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मददगार है। यह शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देने में मददगार है। जिससे यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में बहुत लाभकारी है।यह कॉम्बिनेशन भोजन के बेहतर पाचन और मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही बादाम और काली मिर्च का सेवन करने से आप लंबे समय तक पेट भरा महसूस करते हैं, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करते हैं।

इससे आपको अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग नहीं होती है, साथ ही शरीर से टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। इस तरह यह वजन घटाने और शरीर में स्वस्थ वजन को बनाए रखने में मदद करता है।बादाम में विटामिन ई होता है और काली मिर्च विटामिन सी से भरपूर होती है। दोनों में ही एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जिससे यह त्वचा की कई स्थितियों जैसे सूजन, मुंहासे, दाग-धब्बों और डेड स्किन आदि से लड़ने में मददगार है।

कटरीना कैफ ने सलमान खान की बहनों के साथ खिंचवाई तस्वीर

बुधवार को कटरीना कैफ अपनी खास दोस्त अर्पिता खान शर्मा के घर पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर दर्शन करने पहुंची थी' इस अवसर पर उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई है' कटरीना कैफ अपने पति विकी कौशल के साथ गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंची थी' कटरीना कैफ हर वर्ष सलमान खान की बहन के घर में आयोजित गणपति पूजा में भाग लेती हैं'कटरीना कैफ की फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीरें शेयर की है'

इसमें उन्हें अर्पिता खान के घर से तस्वीरें शेयर करते हुए देखा जा सकता है' तस्वीरों में कटरीना कैफ, मिनी माथुर, अर्पिता खान और अलवीरा खान नजर आ रही है' विकी तस्वीरों में नहीं है' यास्मिन कराचीवाला ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है,

गणपति बप्पा लुकिंग सो क्यूट' इसके अलावा उन्होंने अर्पिता खान का कार्यक्रम में बुलाने के लिए आभार व्यक्त किया है'वहीं कटरीना कैफ अपने पति विकी कौशल के साथ गणेश उत्सव में भाग लेने पहुंची थी' उन्हें हाल ही में फिल्म फेयर अवॉर्ड सेरेमनी में भी देखा गया था' दोनों काफी खूबसूरत लग रहे थे' विकी कौशल को इस अवसर पर बेस्ट ऐक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था' कटरीना कैफ उनका मनोबल बढ़ाती नजर आई' इस अवसर पर दोनों ने किस भी किया' इस अवसर पर विकी कौशल के माता-पिता और उनका भाई सनी कौशल भी साथ में बैठे नजर आए'कटरीना कैफ जल्द मैरी क्रिसमस, टाइगर 3, फोन भूत और जी ले जरा में नजर आएंगी' वह फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम है' वह कई फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभा चुकी है'.

केएल राहुल की खराब फॉर्म पर हर्षा भोगले ने जताई चिंता,कही यह बात

नई दिल्ली। भारतीय टीम ने एशिया कप के दूसरे मुकाबले में हांगकांग को 40 रन से हराकर सुपर-4 में जगह बना ली है। इस मैच में विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इस मैच में सूर्यकुमार यादव ने 22 गेंदों पर 6 छक्के व 6 चौकों की मदद से 261.54 की स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 68 रन बनाए। वहीं, विराट कोहली ने भी फॉर्म में लौटने के संकेत देते हुए 59 रन की नाबाद पारी खेली।हालांकि एक भारतीय बल्लेबाज का फॉर्म इस समय थोड़ा खराब चल रहा है। चोट के बाद वापसी कर रहे केएल राहुल का बल्ला एशिया कप में खेले गए अभी तक दोनों मैचों में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया है। पहले मैच में केएल राहुल शून्य पर आउट हो गए। वहीं, दूसरे मैच में केएल राहुल ने 39 गेंदों पर महज 36 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान केएल राहुल आत्मविश्वास से लबरेज नहीं दिखे।

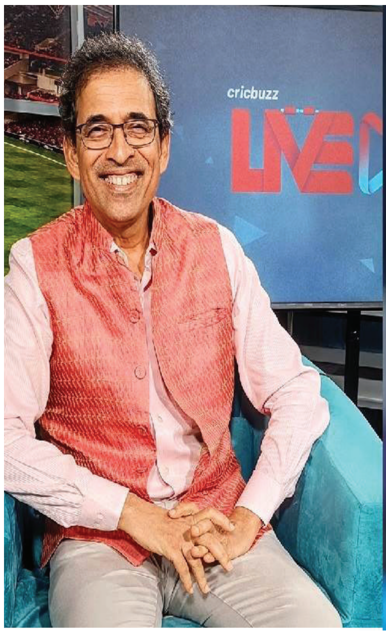

भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के बीच ह्यवॉयस ऑफ क्रिकेटह्न (श्ङ्की ङ्का उङ्क्री३) के नाम से मशहूर कमेंटटर ओर शो होस्ट हर्षा भोगले (ल्नं१२ँ इँङ्क्री ने केएल राहुल के मौजूदा फॉर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केएल को जल्द से जल्द फॉर्म में वापस आना होगा वरना चयनकर्ता उनपर सवाल उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हांगकांग जैसी टीम के आगे 39 गेंद पर 36 रन बनाने सही नहीं है। हर्षा ने कहा, ह्य39 गेंद खेलकर भी केएल राहुल आत्मविश्वास से भरपूर नजर नहीं आए। केएल राहुल को ज्यादा से ज्याद नेट्स पर वक्त बिताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केएल राहुल एक खास खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका खेल फंसा हुआ नजर आ रहा है। केएल राहुल इस पीढ़ी के सबसे अच्छे खिलाड़ियों मे एक हैं। केएल राहुल को अपना डर निकालना पड़ेगा। उन्हें टीम से बाहर निकाल जाने का भी डर अपने मन से निकलने की जरूरत है। हर्षा भोगले ने आगे कहा, ह्यमुझे उम्मीद है कि अगले साल आइपीएल (क्लछ) के दौरान, वह ऑरेंज कैप के बारे में भी नहीं सोचेंगे। बता दें कि इस टीम में दीपक हुड्डा जैसे बल्लेबाज भी मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही आयरलैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाया है।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली, रोहित दूसरे नंबर पर

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने हांगकांग के खिलाफ 31वां अर्धशतक जड़ा। इस मैच में विराट कोहली ने 44 गेंदों पर एक चौके और तीन छक्कों की मदद से 59 रन की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ विराट कोहली ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 31 बार 50 से ज्याद रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में रोहित शर्मा ने अभी तक 27 अर्धशतक बनाए हैं। रोहित शर्मा टी-20 मैच में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। विराट के नाम 101 मैचों की 94 पारियों में 31 अर्धशतक हैं। उनका उच्चतम स्कोर 94* था जो दिसंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ आया थारोहित शर्मा ने 134 मैचों की 126 पारियों में चार शतकों के साथ 27 अर्धशतक लगाए हैं। बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, डेविड वार्नर, मार्टिन गप्टिल और पॉल स्टर्लिंग एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टी-20 में 20 से अधिक पचास या अधिक स्कोर बनाए हैं।

सिंगापुर में जन्में डेविड को मिली ऑस्ट्रेलिया की टी-20 विश्व कप टीम में जगह

नई दिल्ली। सिंगापुर में जन्में आक्रामक बल्लेबाज टिम डेविड को ऑस्ट्रेलिया की टी-20 विश्व कप की टीम में शामिल किया गया है जबकि सीनियर सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को भारत दौरे से विश्राम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को टी-20 विश्वकप और भारत दौरे के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन किया।लंबे शाट मारने के लिए मशहूर 26 वर्षीय डेविड ने 2019 और 2020 में सिंगापुर की तरफ से 14 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जिनमें उनका औसत 46.5 रहा। आइसीसी के नियमों के अनुसार वह तुरंत प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल सकते हैं। डेविड ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में अपने लिए विशेष जगह बनाई है। वह विश्व भर की टी-20 लीग में खेलते हैं। डेविड के माता-पिता ऑस्ट्रेलियाई हैं लेकिन उनका जन्म सिंगापुर में हुआ था। जब वह दो वर्ष के थे तब उनके माता-पिता पर्थ में बस गए थे। इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने डेविड को इस साल के शुरू में 8.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। ऑस्ट्रेलियाई चयनसमिति के अध्यक्ष जार्ज बेली ने बयान में कहा, ह्यटिम डेविड ने विश्वभर की लीग में अच्छा प्रदर्शन करके अपने लिए विशेष स्थान बनाया है और इस कारण उन्हें टीम में जगह दी गई है।आरोन फिंच की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम इस महीने के आखिर में भारत का दौरा करेगी जिसमें वह 20 सितंबर से तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को भारत दौरे से विश्राम दिया गया है। भारत दौरे के लिए चुनी गई टीम में उनकी जगह कैमरन ग्रीन को रखा गया है। पिछले साल विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में केवल एक बदलाव किया गया है तथा मिशेल स्वेपसन की जगह डेविड को टीम में लिया गया है।

उद्धव ठाकरे का वोट बैंक तोड़ेंगे राज ?
BMC चुनाव में BJP चल सकती है बड़ा दांव

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी इटउ के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में एक और सियासी बदलाव आकार लेता दिख रहा है। खबर है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर चचाएं जारी हैं। हालांकि, इसे लेकर दोनों दलों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन लगातार हो रही हाईप्रोफाइल मुलाकात ऐसे संकेत दे रही हैं।मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास शिवतीर्थ पर मिले। इससे एक दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भी राज से मुलाकात की थी। जबकि, मनसे प्रमुख राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने मलाबार स्थित आवास पर पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि भाजपा का मानना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट और राज की पार्टी के साथ वह सेना के मराठी वोट बैंक को अपना बना सकते हैं।इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि बीएमसी चुनाव को लेकर फिलहाल दोनों दलों के बीच चचाएं शुरूआती दौर में हैं। राज में भाजपा को एक प्रखर वक्ता नजर आता है, जो उद्धव ठाकरे और संभाजी ब्रिगेड को आक्रामक होकर टक्कर दे सकता है। इसके अलावा वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को भी हराना जानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एक भाजपा नेता ने कहा, ह्यहो सकता है कि राज ठाकरे सीटें न जीत सकें, लेकिन भाजपा के लिए उनकी रैलियां महाविकास अघाड़ी के खिलाफ माहौल तैयार करने में मदद करेंगी।ह्न उन्होंने यह भी बताया कि मनसे प्रमुख की 10-12 बड़ी रैलियां फायदेमंद साबित हो सकती हैं।एक मनसे पदाधिकारी का कहना है, ह्यमनसे बीएमसी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन भाजपा और शिंदे गुट के साथ गठबंधन उचित होना चाहिए। पार्टी के एक अन्य नेता कहते हैं

URGENTLY REQUIRED FEMALE STAFF
VACANCY VACANCY
ICON OPTICAL GALLERY
Urgently Required Female Staff Accountant Cum Sales Girl For Counter Sell.
Note : Must Have Computer Operating Knowledge
Contact Us : 9819292152
Shop No. 52, R.N.A. Arcade, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai - 400 053
murtaza12152@yahoo.com

TASNEEM COLLECTION
Online Shopping Hub
Only of Ladies Bags, Kurtis, Accessories
Kitchen & Household items
Baby products
Plastic items
And much more......all under one roof

Best business apportunity for housewives
to become reseller & earn at zero investment
Farida Rampurawala :
8898065152
RH 1, C 26 row house number,
Swamy Ayyappam temple road,
Sector. 8, New Mumbai,
Vashi-400 703

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक संपादक – मुर्तुजा मामाजीवाला के द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, युनिट नं. 4, ग्राउंड फ्लोअर, एन. के इंडस्ट्रिअल इस्टेट , ऑफ आरे रोड , प्रवासी इंडस्ट्रिअल इस्टेट के पास , गेट नं. 2, गोरेगाव (पूर्व),मुंबई - 400063 से मुद्रित कर शिव वातुक सेना कासिम नगर नियर लक्ष्मी इस्टेट न्यू लिंक रोड, अधेरी (प),मुंबई -400053 प्रकाशित । संपादक : मुर्तुजा मामाजीवाला मों. 9819199997
■ T.C. NO. MAHHIN10172 ■ ईमेल: newsicon2021@gmail.com ■ newsicon.net